



WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SN: 0131082026

TRAINING NOTICE

DATE: 31/08/2026

भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जिनके संचालन में सार्वजनिक धन का उपयोग होता है। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली संविधान, अधिनियमों, नियमों, शासन की गाइडलाइंस, विभागीय निर्देशों, न्यायालयीन निर्णयों एवं निर्धारित सेवा मानकों द्वारा संचालित होती है। व्यवहार में कानून में निर्धारित प्रावधानों और धरातल पर उपलब्ध सेवाओं के बीच अंतर हो सकता है। नागरिकों को अपने अधिकारों एवं वैधानिक उपायों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण वे उपलब्ध सेवाओं का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद् द्वारा “मिशन न्याय” प्रोजेक्ट की स्थापना 26 अगस्त 2026 को परिषद् की चेयरपर्सन एवं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉ. ज्योति जौगलुजू द्वारा की गई। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 सितम्बर 2026 से प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होंगे। लगभग 100 विषयों को शामिल करने तथा प्रतिवर्ष 10,000 सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विषय की महत्ता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि संबंधित प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। प्रत्येक विषय में विशेषज्ञ एवं अनुभवी प्रशिक्षक मार्गदर्शन करेंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल सदस्यों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। संबंधित विषय में निरीक्षण, जनजागरूकता, अनुसंधान एवं अन्य कार्यों में केवल प्रमाणित सदस्य ही भाग ले सकेंगे। “मिशन न्याय” के प्रथम चरण में 05 विषय शामिल किए गए हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।

The Central Government, State Governments, and Local Governments in India provide citizens with various public services and facilities, for the operation of which public funds are utilized. The functioning of these institutions is governed by the Constitution, Acts, Rules, Government Guidelines, departmental instructions, judicial decisions, and prescribed service standards. In practice, there may be a gap between the provisions prescribed by law and the services available at the ground level. Due to inadequate knowledge of their rights and legal remedies, citizens may not be able to effectively utilize the available services. Keeping this need in view, the World Human Rights Research Council established the “MISSION NYAY” Project on 26 August 2026, under the leadership of Dr. Jyoti Zongluju, Chairperson of the Council and Advocate, Supreme Court of India. Under this project, training sessions will commence from 1 September 2026. A target has been set to include approximately 100 subjects and train 10,000 members annually. The duration of training may be determined by the concerned trainers according to the importance and requirements of the subject. Experts and experienced trainers will provide guidance in each subject. After completion of the training, an online examination will be conducted. Members who successfully pass the examination will be provided with a Training Certificate. Only certified members will be eligible to participate in inspection, public awareness, research, and other activities related to the respective subject. The first phase of “MISSION NYAY” includes 05 subjects, the details of which are given below.

SR	TOPIC	TRAINER NAME	FROM	TIME
01	Indian Right to Information Law	Dr R S Chauhan	01 Sep 2026	06PM-07PM
02	Indian Family Law	Dr Vaishali Mathur	01 Sep 2026	07PM-08PM
03	Indian Education Law	Dr Jatinder Bagga	01 Sep 2026	08PM-09PM
04	Indian Cyber Law	Dr Satyander Kumar	01 Sep 2026	09PM-10PM
05	Indian Labour Law	Dr S K Chaubey	01 Sep 2026	10PM-11PM

Rashmi Bala
Secretary

CLICK THE GIVEN LINK TO
REGISTER FOR “MISSION NYAY”
TRAINING PROGRAM

[HTTPS://RZP.IO/RZP/WHRRRC-06](https://RZP.IO/RZP/WHRRRC-06)

SCAN QR TO
REGISTER
FOR
“MISSION
NYAY”
TRAINING

